

संघीय व्यवस्था में राज्यपालों की भूमिका:
विविध वैधानिक पहलुओं का अध्ययन
(उ० प्र० के विशेष सदर्थ में)

डॉ० आशुतोष पाण्डेय,
एस० प्र०, राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
Email: bins.0280@gmail.com

सारांश

विगत वर्षों में केंद्र व राज्यों के मध्य सबसे अधिक विवादास्पद प्रश्न, राज्यों में राज्यपालों की भूमिका से सम्बन्धित रहा है। न केवल कांग्रेस अपितु मिली-जुली सरकारों सहित भाजपा नीति गठबंधनीय सरकार ने भी अवसर मिलने पर इस पद का प्रयोग राजनीतिक हितों के लिये किया। संविधान निर्माताओं ने भी कल्पना नहीं की थी कि यह पद संघीय सरकार हेतु अभिकर्ता के रूप में उभरेगा। आज स्थिति यह है कि इस पद को समाप्त करने की मांग की जाती है। ऐसा क्यों हुआ? इसका विवेचन प्रस्तुत शोधपत्र में दिया जा रहा है—

मुख्य शब्द— अनुच्छेद 356, सरकारिया आयोग, सहकारी संघबाद, कार्यपालिका, संसदीय शासन प्रणाली

प्रस्तावना

भारत के राज्यों में भी केन्द्र के समान संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के भाग 6 (अनु० 152-213 व अनु० 239-240) में राज्य कार्यपालिका का विस्तार से वर्णन किया गया है। संविधान सभा में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कई प्रकार के सुझाव दिये गये थे लेकिन सभा में यह सुझाव स्वीकार किया कि राज्यपाल का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा हो। ए० के० अय्यर ने इस सम्बन्ध में संविधान सभा में कहा था कि समरूपता की प्राप्ति के लिये, राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद के सदस्यों के बीच स्वस्थ सम्बन्धों की स्थापना के लिये यही अच्छा है कि हम कनाडा के अनुरूप ही करें। इस प्रकार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होता है। लेकिन राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमण्डल के परामर्श से करता है। संविधान यह व्यवस्था करता है कि संसदीय प्रणाली के अधीन राज्यपाल संविधानिक प्रधान होगा। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रीपरिषद में निहित होगा, जो विधिमण्डल के प्रति उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में यदि राज्यपाल प्रत्यक्ष मत द्वारा निर्वाचित होगा तो यह अपने आप को मुख्यमंत्री से वरिष्ठ समझेगा क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र

से चुना जाता है। संविधान सभा में डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति मंत्रीपरिषद में निहित है तब एक और व्यक्ति जो समझता है कि उसके पीछे पूरा प्रांत है और इसलिये वह अपने विवेकानुसार आगे बढ़कर प्रांत के शासन में हस्तक्षेप कर सकता है तो इससे लोकतंत्र विनष्ट हो जायेगा।²

राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा आपातकालीन अधिकार प्राप्त नहीं हैं। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा (अनु० 154(1)) भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। संविधान निर्माता भारत में एक ऐसा संघीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संघवाद की धारणा के आधार पर केंद्र व राज्य में सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकें और प्रशासनिक एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और उनके द्वारा राज्यपाल के पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूर्ति के एक साधन के रूप में की गयी। चतुर्थ आम चुनावों के बाद राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र नियुक्ति के तरीके आदि को लेकर केंद्र व राज्यों में मदभेद उत्पन्न हुए और केंद्र या राज्य के सम्बन्धों के निर्धारण में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद होती चली गयी। राज्यपाल की स्थिति एक विवादास्पद प्रश्न है। कुछ लोगों का कहना है कि राज्यपाल केवल सांविधानिक प्रधान है। इसके विपरीत दूसरे लोगों का कहना है कि राज्यपाल राज्य का वास्तविक शासक है। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धान्तों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रीपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और कोई भी कार्य वह स्वविवेक से नहीं कर सकता।³ डॉ० पायली के अनुसार राज्यपाल मंत्रीपरिषद का सूझ-बूझ वाला परामर्शदाता है जो राज्य की अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा कर सकता है।⁴ एम० एल० सिंघवी के अनुसार, मंत्रीपरिषद के बहुमत की जांच करना वह अपना ऐसा स्वविवेकीय अधिकार समझ सकता है जिससे वह मंत्रीपरिषद के परामर्श के विरुद्ध भी अपनी इच्छा से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है,⁵ साधारणतः वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन असाधारण काल में वह ऐसा कर सकता है। राज्यपाल केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है। वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।⁶

चतुर्थ आम चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। अब संघ प्रणाली का क्रियान्वयन एक दल प्रधान ढाँचे में होने लगा। इन चुनावों के बाद कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त हुआ और अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनीं। इसी अवसर में कई राज्यों में क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक दलों का अभ्युदय हुआ। इस प्रकार के राजनीतिक वातावरण बनने का कारण राज्यों में राज्यपालों की भूमिका को संदिग्ध माना जाने लगा। ऐसी अवस्था में कतिपय राज्यपालों ने तो सुनिश्चित लोकतांत्रिक अभिसमयों का भी पालन नहीं किया और ऐसा आभास मिलता था कि इन्होंने केंद्रीय सरकार के एक एजेंट की भूमिका का निर्वाह करने में ही अपने

कर्तव्य की इतिश्री मान ली। असम में राज्यपाल के पद की विवादास्पद भूमिका 1992 से ही देखी जा सकती है।

राज्यपाल पद को सर्वाधिक विवादास्पद बनाने वाले राज्यपाल हैं, मुख्यतः रोमेश भण्डारी तथा सुंदर सिंह भण्डारी। रोमेश भण्डारी उत्तरप्रदेश के राज्यपाल के तौर पर उसी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात में लगे हुए थे, जिसका परिचय बिहार में सुंदर सिंह भण्डारी ने दिया है। अंतर केवल यही था कि एक बीजेपी की सरकार को हटवाना चाहते थे तो दूसरे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को।

धारा 356 का उपयोग—

संविधान के अनुसार संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये। अनु 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गयी हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। यह संघ सरकार के हाथों में एक ऐसा संवैधानिक अस्त्र है जिससे वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब तक इसका प्रयोग लगभग 120 बार तक किया जा चुका है। अधिकांशतः इसका प्रयोग राजनीतिक कारणों से किया जाता रहा है, यह राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिये केंद्र के हाथ में मजबूत अस्त्र रहा है। सर्वप्रथम इस अनुच्छेद का उपयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। उसके बाद कई राज्यों में इसका प्रयोग किया गया।

संविद सरकारें एवं राज्यपाल का पद तथा धारा 356 का प्रयोग

चौथे आम चुनाव कोमतपत्र के माध्यम से राजनीतिक क्रांति का नाम दिया जाता है, क्योंकि इन चुनावों ने भारत की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इन चुनावों के बाद विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी। जिन तत्वों ने इस स्थिति को जन्म दिया था उनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व था भारतीय संघ के लगभग आधे राज्यों में मिली-जुली सरकारें स्थापित हुई थी जो एक दलीय सरकारों की तुलना में कमजोर थी। 90 के दशक में केंद्र में भी मिली-जुली सरकारों की स्थापना हुई, जिसने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिरता प्रदान की है। मिली-जुली सरकारों की स्थिति में यह स्वाभाविक था कि राज्यपाल अनेक बार स्वविवेक से कार्य करते और राज्यपाल ने जितनी अधिक सीमा तक स्वविवेक से कार्य किया, उतनी ही सीमा तक यह पद विवाद का विषय बन गया। इस प्रकार के विवाद मुख्यतः राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, पदच्युति व विधानसभा को भंग करने आदि प्रश्नों को लेकर उत्पन्न हुए।

पिछले दो दशकों की मिली-जुली भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका विशेष रूप से धारा 356 के सन्दर्भ में काफी विवाद का विषय बनी है। साथ ही इस अवधि में राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। इसका प्रमुख कारण केंद्र व राज्य में पृथक-पृथक

सरकारो का होना है और फिर यदि केंद्र में एक दल की सरकार न होकर गठबंधन सरकार हो, तो राज्यपाल के पद का चर्चा का विषय बनना विवाद का विषय है। मिली-जुली सरकारों ने संसदीय प्रणाली को काफी हद तक प्रभावित किया है। इसमें राज्यपाल का पद संविधान की व्यवस्था का एक अंग न रहकर इसमें राजनीतिक दांव-पेंच का भाव ज्यादा हो गया है। ऐसे कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जबकि राज्यपाल ने संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक में रखकर अविवेकपूर्ण निर्णय लिये जैसे 1967 में हरियाणा, 1970 में बिहार, 1976 में तमिलनाडु और उड़ीसा, 1984 में आंध्रप्रदेश और गुजरात, 1998 में उत्तरप्रदेश और 1999 में बिहार आदि राज्यों में राज्यपाल और केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के यह कृत्य संवैधानिक प्रावधानों व कानूनी स्थिति के सर्वथा विपरीत थे।

उत्तरप्रदेश के संदर्भ में राज्यपाल का पद व धारा 356—

संविधान के अनुसार 356 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यदि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही हो तो उसे हटा कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, पर कई बार इसका प्रयोग राजनीतिक कारणों से किया जाता रहा है। उ0प्र0 में रोमेश भण्डारी ने भाजपा-बसपा संयुक्त सरकार से बसपा के अलग हो जाने पर यह मान लिया कि सरकार बहुमत खो बैठी है। उनको केंद्र के मंत्रीमंडल की मदद भी प्राप्त थी और उन्होंने धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। उन्होंने कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया परंतु उन्हें राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण करना पड़ा जिसमें जगदम्बिका पाल कल्याण सिंह से हार गये और कल्याण सिंह की सरकार बच गयी। क्या यह राज्यपाल की भूमिका का पक्षपाती तथा धारा 356 के दुरुपयोग को नहीं दर्शाता ? उत्तरप्रदेश में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति केन्द्रीय मंत्रीमण्डल की उस पर सहमति, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रीमण्डल की सिफारिश को पुनर्विचार के लिये वापस लौटाना और मंत्रीमण्डल द्वारा इसके बाद अपना निर्णय बदलने से जहाँ राष्ट्रपति के0आर0 नारायणन ने भारतीय लोकतंत्र में एक इतिहास रचा वही राष्ट्रपति शासन के लिये उत्तरदायी अनु0 356 और राज्यपाल का पद सुर्खियों में आया जिससे राज्यपाल पद की गरिमा तथा अनु0 356 के क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ ?

क्या धारा 356 का उपयोग-दुरुपयोग उचित है ?

यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद का ठीक से पालन नहीं किया गया है तथा हर प्रधानमंत्री के शासन काल में दुरुपयोग करने की कोशिश की गयी है, तो क्या यह मान लिया जाये कि इसका अब तक समस्त प्रयोग नैतिक व संवैधानिक दोनों दृष्टियों से गलत था ? परंतु ऐसा कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि भारत में कई बार राज्यों में ऐसी समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं जब राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिये इसका प्रयोग करना पड़ता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में राज्यों की स्वतंत्रता की मांग उठती रहती है। अतः इस अनुच्छेद के माध्यम से इस पर रोक लगायी जा सकती है। इन परिस्थितियों में माना जाता है कि अनु0 356 के उपयोग को लेकर एक धारणा कायम नहीं की जा सकती है। इसके सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी

है। जरूरत है ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग की। इसके दुरुपयोग के खिलाफ दो दबाव बने। एक, अदालत हस्तक्षेप कर ठोस आधार न होने पर बर्खास्तसरकार को बहाल कर सकती है, दूसरा संवैधानिक भावना के खिलाफ होने के कारण राष्ट्रपति केंद्र सरकार को कठघरे में ला सकते हैं। माना जाता है कि अगर दोनो संवैधानिक संस्थायें इसी प्रकार क्रियाशील रहीं, तो अनु0 356 का दुरुपयोग बहुत हद तक रुक सकेगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव—

वर्तमान समय में राज्यपाल का पद इतना विवादास्पद तथा संदिग्ध हो गया है कि विशेष रूप से धारा 356 के सन्दर्भ में जिसका प्रयोग राज्यपाल राष्ट्रपति से करवाने के लिये अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। धारा 356 के दुरुपयोग ने इसकी सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यदि शासनतंत्र की विफलता राष्ट्रपति के समाधान का कोई अर्थ नहीं है तो इन्हें संविधान से अलग कर संसद का समाधान सर्वोपरि मान लेना चाहिये। राज्यपाल तथा राजनीतिक दलो को यह नहीं भूलना चाहिये कि लोकतंत्र में लोक की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज आवश्यकता स्वार्थसिद्धि एवं सत्ता के मोह से ऊपर उठकर लोकहित की रक्षा करने की है। आज आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल इस संवैधानिक साधन का प्रयोग सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय एवं संविधान की भावना को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग किया जाये। अतः आवश्यकता है कि अनु0 356 के संदर्भ में राजनीतिक दलों के मध्य आम सहमति बनायी जाये जिससे संविधान एवं राष्ट्रीय अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके।⁷ राज्यपाल की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास बहुत से विद्वानों ने किया है। डी0डी0 बसु के शब्दों में, "राज्यपाल केवल दिखाने का प्रधान नहीं होगा। अगर वह कार्यशील तथा अच्छा राज्यपाल है तो सत्तारुढ़ दल के विरोधियों से सम्पर्क साधकर उन्हें कई अच्छे कार्यों के लिये राजी कर सकता है और प्रशासन को सुचारु बना सकता है।"⁸ डॉ0 पायली का कहना है, "यह एक कड़ी है जो संघ तथा राज्यों को जोड़ता है और संघ राज्य के सम्बन्धों को निर्धारित करता है। वह संविधान का आवश्यक भाग है जो एक आवश्यक उद्देश्य को पूरा करता है तथा आवश्यक सेवा प्रदान करता है।"⁹ डॉ0 बी0 जी0 खैर ने संविधान सभा में कहा था कि एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है और एक बुरा राज्यपाल बहुत दुष्टता भी कर सकता है यद्यपि संविधान में उसको बहुत कम शक्ति दी गयी है।"¹⁰

अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है और आवश्यकता है कि वह अपने पद का प्रयोग अनु0 356 में वर्णित संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार ही करे जिससे राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनी रहे।

सन्दर्भ

1. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, CAD खण्ड-7, पृ0 432
2. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, CAD खंड-7, पृ0 432
3. डॉ0 अम्बेडकर, CAD खंड-7, पृ0 430

4. एम0 वी0 पायली, *इंडियाज कांस्टीट्यूशन*, एसचन्द्र प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ0 **234**
5. एम0 एल0 सिंघवी, *स्टेट्समैन*, 12 नव0 1967
6. एम0 बी0 पायली, *इण्डियाज कांस्टीट्यूशन*, एसचन्द्र प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ0 **238**
7. एन0 एस0 गहलोत: *भारतीय राजनीतिक व्यवस्था*: दशा एवं दिशा, 1996, South Asia Books, पृ0 **82**
8. D. D. Basu, *Introduction to the Constitution of India*, 21st Edition, LexisNexis Publication, 2015, Page No. **254**
9. एम0 वी0 पायली, *इंडियाज कांस्टीट्यूशन*, एसचन्द्र प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ0 **240**
10. बी0 जी0 खैर, *CAD*, खंड सात, पृ0 **434**